पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों का निस्तारण तेजी से किए जाने के निर्देश दिए

जनसुनवाई प्रणाली में जनपद स्तर पर लगभग 15 हजार अधीनस्थ अधिकारियों को शामिल करने के निर्देश

नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू

अब जनता जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ–साथ जनपद, तहसील, ब्लॉक व थाना स्तरीय अधिकारियों के पास शिकायत सीधे ऑनलाइन दर्ज करा सकेगी

इस व्यवस्था से जनता को स्थानीय अधिकारी के समक्ष शिकायत सीधे उपलब्ध कराने का अवसर प्राप्त होगा

मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जनसुनवाई प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) पर जनता के लिए नई सुविधा उपलब्ध

लखनऊ : 08 सितम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनता की शिकायतों का तेजी से निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जनसमस्याओं का उसी स्तर पर निस्तारण किया जाए, जिस स्तर पर निस्तारण अपेक्षित है। उनके निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने जनसुनवाई प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) पर आम जनता के लिए नई सुविधा उपलब्ध करायी है। अब जनता सीधे जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ–साथ अन्य जनपद स्तरीय, तहसील स्तरीय, ब्लॉक व थाना स्तरीय अधिकारियों के पास अपनी शिकायत सीधे ऑनलाइन दर्ज करा सकेगी। इस नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि उनके अधीनस्थ अधिकारी जनता की शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग

से कम से कम समय में करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक ढंग से निस्तारण नहीं करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित किया जाएगा। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में संवेदनशील एवं पारदर्शी प्रशासन देने के लिए संकल्पबद्ध है।

यह जानकारी देते हुए आज यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में जनसुनवाई प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) पर जनपद स्तर पर ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज कराने हेतु 150 अधिकारियों का ही विकल्प उपलब्ध था। उसे मुख्यमंत्री जी ने अब बढ़ाकर राज्य के लगभग 15,000 जनपद व अधीनस्थ अधिकारियों को शामिल करने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि शिकायत ऑनलाइन तरीके से दर्ज कराने नई व्यवस्था से जनता को स्थानीय अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत सीधे उपलब्ध कराने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही, स्थानीय अधिकारी को भी शिकायत सीधे कम समय में प्राप्त होने के कारण उस पर कार्रवाई करने में आसानी होगी।

प्रवक्ता ने बताया कि सांसदों व विधायकगण द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित की जाने वाली शिकायतों व संदर्भों को सीधे जनपद में नियुक्त विभिन्न विभागीय अधिकारियों को प्रेषित किए जाने का विकल्प उनके आई0जी0आर0एस0 लॉगइन आई0डी0 पर उपलब्ध करा दिया गया है।

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

PN-CM-IGRS-08 September, 2017